श्री मधु लिमये: स्पीकर ने अस्वीकार भी नहीं किया है इसी लिये जानकारी चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That means the Speaker is seized of the matter, and as you have said, if some assurance is given by the Government and if that is not carried out . . .

श्री मधु लिमये : जब विशेष चीज आई है तब इस को मैंने उठाया है, मेरे पास बहुत से सबत हैं, पत्र हैं, भाषण हैं, मैं अभी उन में नहीं गया हूं . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: At this time how can you take it up?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : देश का यह बहुत कीमती वक्त है इस से देश का नुकसान हो रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You take up the matter with the Speaker and then bring it up before the House. That is the only procedure I can suggest.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Forget for the moment the privilege motion. Is it not open to the Minister to say that what appeared in the press is wrong?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): The meeting about which the report has appeared in the paper is supposed to be a secret meeting.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What appeared in the press cannot be said to be authoritative.

श्री मधु लिमये : आपके यहां क्या कोई चीज गुप्त, सीक्रेट बचनी है आपके ही मंत्री आ कर बताते हैं। क्या आप इस को डिनाई करते हैं, क्या आपके कहने का यह मतलब है कि पेट्रियट में जो खबर छपी है वह गलत है हिम्मत है तो कहिये ?

डा० राम सुभाग सिंह : मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूं कि कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होनी है वह बिलकुल गुप्त बैठक होनी है।

श्री मधु लिमये : मुझे इस से क्या मतलब। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो बात छपी है वह ठीक है या नहीं।

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): May I make a submission? What is supposed to have happened at the meeting of the Congress parliamentary party executive (*Interruption*).

I would like to draw the attention of Shri Madhu Limaye to the fact that the discussion on this subject was not conclusive, and it has been postponed. Further, he cannot take cognizance of what happens at party meetings or private meetings. It is only what happens in this House which matters.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I entirely agree that whatever may appear in the press regarding party squabbles anywhere on any matters that are discussed, whether in the SSP or CPI or the Congress, we cannot take those reports to be authoritative.

14.11 hrs.

ENEMY PROPERTY BILL—*Contd.*

Clause 7—(*Payment to Custodian of money otherwise payable to an enemy, enemy subject or enemy firm*)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): I beg to move:

Page 3, lines 22 and 23, *omit* 'unless otherwise ordered by the Central Government'. (2)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The amendment is now before the House.

श्री बेणी शंकर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उस क्लाज को भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :

"7(1) Any sum payable by way of dividend, interest, share profits or otherwise to or for the benefit of an enemy or an enemy subject or an enemy firm, shall, unless otherwise ordered by the Central Government, be paid by the person...... to the Custodian . . .".

इस वाक्यांश से सरकार कस्टोडियन को एक हाथ से जो देती है, वह दूसरे हाथ से ले लेती है । मेरी समझ में नहीं आता कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसी कम्पनी का जिसका डिवीडेन्ड एनिमी सब्जेक्ट के एकाउन्ट में जमा होना चाहिये कस्टोडियन को न दिला कर किसी और को दिलाने के लिये कानून में हक चाहती है । हम जानते हैं कि यह भ्रष्टाचार का युग है और इसमें ऐसे प्राविधान का कितना दुरुपयोग हो सकता है । आखिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर्स हैं जो अफसरों की सलाह से काम करते हैं । और वे आफिसर अपने नीचे वालों सलाह से काम करते है इसमें प्राविधान से इस बात की सम्भावना हो सकती है कि नीचे वालों को कोई प्रभावित करले और जो रुपया कस्टोडियन के पास जाना चाहिए वह किसी और को जोकि एनिमी का भाई बन्धु या संबंधी हो सकता है, दिला दें । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस वाक्यांश को इस क्लाज में से निकाल दिया जाए ।

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): If these words are omitted as suggested by the hon. Member, there will be a total prohibition on persons by whom money is payable to a person whose property is vested with the Custodian from paying the money altogether. That is why we have reserved this discretion with Government to see that the person who has to pay money does not have to pay in any wrongful manner and this discretion of the Government will be justly exercised. The hon. Member has mentioned that Government's discretion is exercised in consultation with the officials and others. That is part of the democratic system that we have.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

Page 3, lines 22 and 23,—*omit* 'unless otherwise ordered by the Central Government'. (2)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up clause 8. I would request hon. Members to be very brief.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): May I request that when we are discussing Bills at least, more time should be given? What is happening is that on all things we are asked to be brief, on adjournment motions we are asked to be brief, on Bills we are asked to be brief and so on . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member was present in the Business Advisory Committee, and he had fixed the time there. Now, I cannot go back on that decision.

SHRI S. M. BANERJEE: It is true that I was there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can take it up at the next meeting of the Business Advisory Committee.

SHRI S. M. BANERJEE: But I may submit that when the Business Advisory Committee fixes time, we do not know that so many amendments will be moved. So, when a Member moves an amendment, he should be given

[Shri S. M. Banerjee]

full chance to speak. I know that on this particular Bill we are very much short of time. But there are other Bills which are coming up and when amendments are moved, the Members moving those amendments should be given some time. I find that the who'e Parliament is becoming brief on every matter; let us not be so brief in everything; at least with respect to Bills, let us express ourselves to some extent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I fully share his views that so far as Bills are concerned, they must be thoroughly discussed and gone into. But the time-factor is important. 3 hours were allotted for this Bill and we have already exceeded 3 hours. We may take another hour more on this. I am trying to accommodate and give opportunity to every Member who has to say something about it.

Clause 8—(*Powers of Custodian in respect of enemy property vested in him*)

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I beg to move:

Page 5, *omit* lines 7 and 8. (3)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The amendment is now before the House.

श्री बेणी शंकर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री स० मो० बनर्जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि असल में जब क्लाज बाई क्लाज बहस होती है तभी हम आपके सामने बिल की बुराइयां और खामियां ला सकते हैं साधारण बहस में सभी बातें नहीं आ पाती हैं। इसलिये आगे से जब इस प्रकार किसी बिल पर बहस हो तो उचित समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने इस संशोधन के जरिए यह चाहता हूं कि क्लाज 8, पेज 5 पर जो यह वाक्यांश हैं :

"make such other payments out of the funds of the enemy as may be directed by the Central Government.".

इनको निकाल दिया जाए। इसमें भी वही बात है। केन्द्रीय सरकार सभी प्रकार के खर्चे गिनाकर फिर चाहती है कि वह जैसा चाहे वैसा कर सके।

आप इस क्लाज के सब क्लाज (8) को देखें :

"8(1) With respect to the property vested in the Custodian under this Act, the Custodian may take or authorise the taking of such measures as he considers necessary or expedient for preserving such property and where such property belongs to an individual enemy subject, may incur such expenditure out of the property as he considers necessary or expedient for the maintenance of that individual or of his family in India.".

कैस्टोडियन सरकार का आदमी है और सरकार को उस पर पूरा भरोसा भी होगा अन्यथा उसकी नियुक्ति ही क्यों की जायेगी। इस क्लाज़ के अन्तर्गत सभी खर्चे हैं :

"to take action for recovering any money due to the enemy;".

यह सब होंगे। लेकिन केन्द्रीय सरकार आगे फिर अधिकार ले लेती है :

"make such other payments out of the funds of the enemy as may be directed by the Central Government.".

लेकिन मुझे भय है कि इस क्लाज के रहते हुए जो एनिमी सब्जेक्ट्स की प्रापर्टी है उससे जो आय होती है उसे हमारी सरकार दूसरे कामों में भी लगा सकती है। आज वोटों का युग है। मैं बड़े अदब के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जो कल तक भाई थे लेकिन आज हम पाकिस्तान को शत्रु कहते हैं। हमारे समाने

ऐसे भी उदाहरण हैं कि एक भाई यहां है और दूसरा भाई पाकिस्तान में है चचा यहां है और भतीजा पाकिस्तान में है बीबी यहां और मियां पाकिस्तान में है । इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे मौके आ सकते हैं जब किसी बहाने से, जिसको हम शत्रु कहते हैं उसकी प्रापर्टी की आमदनी किसी दूसरे आदमी को दिला दी जाए क्योंकि हमारी सरकार वोटों के लिये बड़ी लालायित रहती है । मुझे भय है कि कहीं वह यह पैसा भी अपने उसी उद्देश्य को पूरा करने में न खर्च कर डाले । इसलिये यह सरकार अपने हाथ में और अधिक पावर लेना चाहती है । मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार वोटों के लिये लालायित है तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य की जो पार्टी है वह वोट नहीं चाहती है । इसमें वोटों का कोई सवाल नहीं है । सवाल यह है कि इसमें बहुत से जो पहले के क्लाजेज हैं उनमें लिखा हुआ है कि किस तरह से खर्चा किया जा सकता है । इसके बावजूद हो सकता है कोई ऐसा खर्चा निकले जो उसमें पूरी तरह से कवर न होता हो । उसके लिये इस क्लाज की जरूर होगी ताकि वह खर्चा किया जा सके । इसके दुरुपयोग होने का कोई प्रश्न नहीं है । इसलिये मुझे दुख है कि माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसको मैं नहीं मान सकता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the amendment to vote. I have to put only amendment No. 3 to vote, because the other amendment, namely amendment No. 8 standing in the name of Shri Abdul Ghani Dar has not been moved since the hon. Member is absent.

The question is:

Page 5, *omit* lines 7 and 8.

Let the Lobby be cleared. (3)

The Lok Sabha divided:

Division No. 5] **[14.23 hrs.**

Amin, Shri R. K.
Chauhan, Shri Bharat Singh
Daschowdhury, Shri B. K.
Dipa, Shri A.
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Maiti, Shri S. N.
Meena, Shri Meetha Lal
Mody, Shri Piloo
Mohamed Imam, Shri J.
Naik, Shri R. V.
Ram Charan, Shri
Ramamoorthy, Shri S. P.
Ramamurti, Shri P.
Ranga, Shri
Saboo, Shri Shri Gopal
Shah, Shri T. P.
Sharda Nand, Shri
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri J. B.

NOES

Babunath Singh, Shri
Barua, Shri R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhargava, Shri B. N.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Birua, Shri Kolai
Bohra, Shri Onkarlal
Chatterji Shri Krishna Kumar
Dass, Shri C.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar

Ganesh Shri K. R.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Jadhav, Shri V. N.
Kamble, Shri
Kesri, Shri Sitaram
Kinder Lal, Shri
Kureel, Shri B. N.
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahajan, Shri Vikram Chand
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mishra, Shri G. S.
Mohammad Yusuf, Shri
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Anantrao
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. D.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Radhabai, Shrimati B.
Ram Subhag Singh, Dr.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Reddy, Shri Ganga
Rohatgi, Shrimati Sushila
Sambasivam, Shri
Sant Bux Singh, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
*Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri Nawal Kishore
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sursingh, Shri
Tiwary, Shri K. N.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result** of the division is: Ayes 20 Noes 62.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9—(Exemption from attachment, etc.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause 9 now. Are you moving my amendment?

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 9 amendment is the same. Only one will be moved.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I move:

Page 5, line 12,—

after "shall" *insert* "not" (4).

*Wrongly voted for '*NOES*'.

**The following Members also recorded their votes:—
AYES: Sarvashri Abdul Ghani Dar, Lobo Prabhu, G. C. Naik and Beni Shanker Sharma.

श्री वेणी शंकर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज 9 को आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :

"All enemy property vested in the Constodian under this Act shall be exempt from attachment, seizure or sale in execution of decree of a civil court or orders of any other authority."

मैं अपने संशोधन नम्बर 4 द्वारा "शैल" के बाद शब्द "नौट" इंसर्ट कराना चाहता हूं और यदि वह स्वीकार कर लिया जाय तो फिर क्लाज इस प्रकार रहेगा :

"All enemy property vested in the Custodian under this Act shall not be exempt from attachement seizure or sale in execution of decree of a civil court or orders of any other authority".

उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो हमारी सरकार यह एनिमी प्रापरटी से जो आय होगी उसको अपने विशेषाधिकार से जिस किसी को चाहे देना चाहती है वहीं वह दूसरी ओर अपने इस क्लाज 9 के द्वारा उन लोगों को वंचित रखना चाहती है जोकि उस के पाने के असली हकदार हैं। अब अगर कोई सिविल मामला किसी एनिमी सब्जेक्ट पर पहले से चल रहा है और उसकी डिक्री हो चुकी है तो क़ानून के मुताबिक उसको हक़ है कि सिविल कोर्ट की डिक्री की तामीली में अटैचमेंट आदि करा सके लेकिन इस क्लाज के द्वारा सरकार एटैचमेंट वगैरह से शत्रु सम्पत्ति को अलग रखना चाहती है और वह चाहती है कि किसी भी हालत में उस व्यक्ति को उसका जायज हक़ न मिले। मैं नहीं समझता कि सरकार को इस तरह का अधिकार क्यों दिया जाये। मैं चाहता हूं कि मेरे अमेंडमेंट द्वारा सुझाये गये "नौट" शब्द को "शैल" शब्द के आगे जोड़ दिया जाये ताकि सरकार को इस तरह का कोई हक़ नहीं प्राप्त हो जिससे वह सिविल कोर्ट की डिक्री के द्वारा प्राप्त हक़ों से किसी पावने दार को वंचित कर सके।

श्री बिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्य को ऐसी इस में क्या दिक्कत अनुभव हो रही है जो कि उनका इस में अमेंडमेंट आया है। आप जानते हैं कि कस्टोडियन के पास यह सम्पत्ति रहेगी और आज जब कि उस सम्पत्ति का मालिक यहां पर नहीं है या उसका इंतजाम नहीं कर सकता और अब अगर कोई व्यक्ति उस के खिलाफ मुकद्दमा दायर करे और चूंकि वह मालिक तो यहां पर है नहीं और कोर्ट का उस पर एक्स पार्टी डिसीशन हो जाये तो जाहिर है कि उस शख्स की प्रापरटी पर असर आयेगा और हम यह क्लाज सिर्फ उसकी सुरक्षा की दृष्टि से रख रहे हैं ताकि उसके बारे में कोई अटैचमेंट वगैरह न हो सके लेकिन जहां तक औरों के क्लेम का सवाल है वह तो रहेगा ही, वह तो रजिस्टर्ड है और वह कहीं नहीं चला जायगा। जो हमारे नागरिक हैं उनकी सम्पत्ति या उनका कोई हक़ इससे चला जायेगा ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं माननीय सदस्य से फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस पर वह फिर विचार करें कि वाक़ई में वह उसको जरूरी समझते हैं या नहीं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : जरूरी इसलिये है कि जिसने सिविल कोर्ट में उजरदारी की है और जिसके फेवर में सिविल कोर्ट ने डिक्री दे दी है वह उसे एक्जीक्यूट नहीं करवा पायेगा। उस नागरिक से जिसे डिक्री मिली है उसका हक आप छीन रहे हैं।

श्री बिनेश सिंह : यही तो मैंने अभी समझाया कि हम किसी का भी अधिकार नहीं छीन रहे हैं। उसका अधिकार भी सुरक्षित रहेगा लेकिन जिसकी कि सम्पत्ति है और जो कि यहां मौजूद नहीं है, इसके जरिए उसके भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

श्री बेणी शंकर शर्मा : आपके सिविल कोर्ट जब डिक्री देते ह तो उसे एक्जीक्यूट होना चाहिए लेकिन उस से आप एग्ज़ेम्पट कर रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : कोर्ट की डिक्री एक्स पार्टी भी हो सकती है क्योंकि जैसा मैंने कहा उस जायदाद का मालिक अर्थात् दूसरी पार्टी यहां मौजूद नहीं है और इसलिए हम यह चीज कर रहे हैं ।

श्री बेणी शंकर शर्मा : अपनी अदालतों में आपको विश्वास होना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will put the amendment to the vote.

Amendment No. 4 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 17 were then added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: On clause 18, are you moving your amendment Mr. Sharma?

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I am not moving.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you moving your amendment, Mr. Dar?

SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon): I am also not moving.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then I will put clause 18 to the vote.

The question is:

"That clause 18 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 25 were also added to the Bill.

Clause I—(*Short title, extent, application and Commencement.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Clause 1—there are two amendments. They are the same: one is by Shri Beni Shanker Sharma and the other is by Shri Srinibas Misra. Are you moving it, Mr. Sharma?

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Yes. I move:

Page 1, lines 4 and 5,—*omit* "except the State of Jammu and Kashmir". (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is the same; Shri Sharma is moving it. If he has any submission to make, I will permit Mr. Misra also to speak.

श्री बेणी शंकर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट नम्बर 1 के द्वारा बिल के पेज 1 पर लाइंस 4 और 5 में से 'एक्सेप्ट दी स्टेट ओफ जम्मू ऐंड काश्मीर" ये शब्द हटाना चाहता हूं । चूंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता । इस सम्बन्ध में सदन में कल काफी चर्चा हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक मुझे इस फिकरे का अर्थ समझ में नहीं आया । आज सरकार घरों की मुंडेरों से नहीं हिमालय की चोटी से चिल्ला-चिल्ला कर कहती है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है । वहां एक बम के धड़ाके से सारा हिन्दुस्तान कम्पायमान हो गया । काश्मीर की पुकार सुन कर सारे देश के ल [illegible] काश्मीर पहुंच गये और उस की रक्षा के लिये हमारे हजारों जवानों

ने अपने प्राण गंवाये। इस हालत के होते हुए और जब मंत्री महोदय भी मानता है कि काश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है लेकिन हमारा यह कानून जम्मू काश्मीर स्टेट पर लागू नहीं होगा तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

मेरे मित्र श्री श्रीनिवास मिश्र ने कल कहा था, और मैं उन से सहमत हूं, कि हमारे संविधान में ऐसा कोई धारा नहीं है जो इस में अड़चन डालती है। लेकिन अगर कोई ऐसा धारा हो भी तो उस के हटाने में कितनी देर लगती है? आज कांग्रेस की सरकार है और उस के सदस्यों का बहुमत है, हम भी उन के साथ हैं। तब इस तरह का जो व्यवधान हो उस को हटाने में पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब इस ओर के सदस्य भी कहते हैं और उस ओर के भी सदस्य कहते हैं कि इस सदस्य कहते हैं कि इस कानून में यह बात बेतुकी लगती है कि यह जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होगा, तो सरकार के लिये इसमें डरने की क्या बात है?

मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी इस नीति के कारण ही आज रूस भी हमारा साथ नहीं देता। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो वीर है, दिलेर हैं, साहसी हैं, संसार उनका ही साथ देता है। बीस वर्षों में भी हम इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाये। विश्व भर को हम कहते आये कि काश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। फिर हमारे कानूनों को वहां लागू करने में ऐसी कौन सी दिक्कत है यह मैं नहीं समझ पाता हूं। यह हमारे शत्रुओं को उत्साहित करता है और वे सोचते है कि हमारे मन में ही दुविधा है जब कि कश्मीर हमारा है या नहीं तब वह भी चाहें तो उस पर दवा कर सकते हैं। आज यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं चाहूंगा कि हम सोचें और गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मेरी धारणा है कि अगर उस तरफ के सदस्यों को वोटिंग की स्वतन्त्रता दी जाये तो वे हमारे साथ होंगे।

एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में लड़ाई हुई। वहां शत्रु सम्पत्ति काफी है। लेकिन अभी तक उस पर अधिकार किया गया है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं समझता हूं कि स्टेट को किसी कानून के अन्तर्गत उसे ऐसा अधिकार नहीं है। स्टेट ने भी कोई कानून नहीं बनाया है जिस से वह शत्रु सम्पत्ति पर अधिकार कर उसको सम्भाल सके। जब स्टेट ने कोई ऐसा कानून वहां लागू नहीं किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यह कानून बना रही है, तो जहां सब से ज्यादा शत्रुओं की सम्पत्ति हो सकती है और जो प्रदेश हमारा अविभाज्य अंग है, उस को इस कानून के दायरे से छोड़ देना कहां तक जायज है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को मान ले।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Mr. Deputy-Speaker, Sir, yesterday I had occasion to refer to this amendment of mine. I would not like to repeat that but the hon. Minister whispered towards the last part that this clause was under the powers vested in the Central Government under the residuary entry of List I. He should have seen that the residuary entry is applicable only to such cases where there is no provision in any other entry. Entries I and 15 of List I refer to matters which come about during war. So, with this matter, enemy property, coming under entries I and 15 of List I, the residuary entry will not apply. If once it is conceded that it comes under entry I or entry 15 of List I, then it is applicable to Jammu and Kashmir. There is no bar. In order to find out a bar he says that it will come under the residuary entry, which is not correct. However much he may try, it is not correct. It is the timidity of

[Shri Srinibas Misra]

the Ministry that stands in the way. They think that they have got some majority. They have got a majority only in hands and eyes. They also want majority in confusion and bungling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Constitution is not interpretted by majority or minority.

SHRI SRINIBAS MISRA: That is exactly my submission. That is what I am trying to say. Please look to sub-clause (2) of clause (1). It says:

> "It entends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir . . ."

In the same sub-clause it is also said:

> "and it applies also to all citizens of India outside India . . ."

Is it not bungling? If it applies only to India minus the State of Jammu and Kashmir, is it applicable to Jammu and Kashmir which is in the occupation of Pakistan or Pakistan-occupied area of Jammu and Kashmir? There was a case recently which went to the Federal Court where Pakistan challenged the jurisdiction of Pakistani courts in that portion of Jammu and Kashmir. Is it within the jurisdiction of Indian sovereignty? Will it be applicable to persons who live in India and have lands in that portion of Jammu and Kashmir? Will it be applicable to persons living in that portion of Jammu and Kashmir but who have property here? To whom will it apply? By implication the Bill seems to suggest that Jammu and Kashmir is not a part of India. Taking these two, it will apply only to India minus Jammu and Kashmir. But it is, at the same time, applicable to all citizens of India. Taking these two together the Bill seems to suggest that the citizens of Jammu and Kashmir are not citizens of India.

Now, Sheikh Abdullah did not want to say that he is a citizen of India. That was taken exception to by this House and the ministers also shed some crocodile tears about it. They said, it is bad that he did not want to say that he is a citizen of India. They agreed that he is doing something which is not proper. When Sheikh Abdullah and Kashmir he is not a citi-Jammu and Kashmir he is not a citizen of India, impliedly this Bill wants to support Sheikh Abdullah's stand. Can it be conceived that it will apply to all citizens of India and not to Jammu and Kashmir? It is creating confusion. Why don't you say that it will not be applicable to the citizens of Jammu and Kashmir. In one breath you say that it will apply to all citizens of India and citzens of India living outside India—say. Honolulu. Citizens living in Honolulu are subject to this Act. But what about Jammu and Kashmir? Are not the people living there citizens of India? Will it not apply to them, They should have made it clear in the Bill itself where it is applicable, to which persons it is applicable and to which territory it is applicable. But by saying this in a confused manner they have confusal both the things. I think the Minister should have, when this matter was raised yesterday, examined this point and come forward with certain clarifications to make this matter clear. He cannot leave this matter in this way so that there will be litigations challenging the Constitution and so many other things. Only a reading of that sentence will show that it is applicable to all citizens of India but not to Jammu and Kashmir. You can exclude the citizens of Jammu and Kashmir from the point of view of this legislation but you cannot say it is applicable to all citizens of India but not to Jammu and Kashmir.

SHRI DINESH SINGH: Mr. Deputy-Speaker, Sir, we had an occasion to discuss this matter yester in every detail and the House also expressed its views on it in the form of a voting. It is the same matter which we are again discussing in this form. I had mentioned to hon. Members yesterday that so far as the sentiments are concerned we are entirely with them in this that there should not be any differentiation as such. But here the situation is somewhat different. We have got a Constitution and we have got to function within the Constitution. In our opinion, it would be unconstitutional to extend this Act to Jammu and Kashmir, according to the provisions as they exist in the Constitution today. If they are removed tomorrow, it will be an entirely different situation. We are not in this Bill at this stage discussing its desirability or not. That is an entirely separate matter.

I tried to explain yesterday that this Bill only sought to continue the situation that already exists in respect of enemy property that had been seized. I can appreciate all the refineries that the hon. member tried to bring in and we can have at a suitable time a discussion on that matter. But it would be not in keeping with the provisions of the Constitution as it exists today to include Jammu and Kashmir, because the subject-matter of this Bill has been brought in under entry 97 of the Union List. which precludes the State of Jammu and Kashmer. Therefore, we have got to conform to the Constitution.

श्री रवि राय (पुरी) : कानून मंत्री से बात कर लें, कनफ्यूशन दूर हो जाएगा।

श्री दिनेश सिंह : उसकी आवश्यकता नहीं है। सब से मैंने बात कर ली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस वक्त सवाल जज्बात का या हमारे ख्यालात का नहीं है। जो कानूनी स्थिति है, जो संविधान है उसके अनुसार हमें काम करना है। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जम्मू काश्मीर में इस कानून के तहत कोई एनीमी प्रपार्टी सीज नहीं की गई है। इसको वहां एप्लाई करने का फिलहाल सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि.....

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: (Kendrapara): The point raised by the hon. member is, it is applicable to all citizens not only living in India, but outside also. If Jammu and Kashmir is excluded, will this Bill be applicable to the Indian citizens living in Jammu and Kashmir or not. How do you reconcile these two.

SHRI DINESH SINGH: I do not see how this difficulty arises at all. It applies to all India citizens. I do not know why the hon. member has any doubt in his mind. It is entirely in his mind, not in our mind. We are only concerned with such property in Jammu and Kashmir and I explained at great length that such property was not seized in Jammu and Kashmir. It applies to all citizens. I would beg of the hon. member not to have any doubts in his mind about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put amendment No. 1 to the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DINESH SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): Sir, the Bill we are now passing into law should be a Bill only for a limited duration. Such a Bill should not be on the statute-book for all times to come. Aleary the powers envisaged in the Bill have been exercised by the Government from 1962. From 1962 till now, the few lakhs worth of Chinese property should have been disposed of. The minister has not stated why it has taken him so long for disposing of this few lakhs forth of Chinese property from 1952 to 1968. I would have been happy if in clause 1(3), there would have been other sentence saying, "it shall remain in force up to 10th July 1971." It should have been indicated in the Bill that it is only for temporary duration and that the Government has no intention of perpetuating it for all times to come.

In any case, I would suggest that this Bill should have been accompanied by a report of the Minister stating what are the properties that will come under this category, how they have been managed so long, in what way they have been managed, what has happened to the properties uptill now and in what condition they are now. The Government has not provided us with a report like that. I hope, after this Bill is enacted into law, the Minister will take as little time as possible to provide Parliament with a report of that kind.

श्री शिव नारायन (बस्ती) :

जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजो संग।

जो संग राखत बने तो करु राखअ पंग ।।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ग्राटिकल 370 जो हमारे संविधान में है, वह एक बोझ है, देश की छाती पर ग्रौर उसको ग्राप रिमूव करें। रोज रोज जो ग्राप बिल लाते हैं उस में ग्राप जम्मू काश्मीर को वरियत देते हैं। कितने दिन तक ग्राप ऐसा करते रह सकते हैं। यह देश को कहां ले जाएगा। इस ग्राटिकल को ग्राप हटायें। यह मुसीबत बना हुग्रा है। यह हमारे मिनिस्टर साहब के रास्ते में रुकावट है। मैं शर्मा जी के साथ सहमत हूं ग्रौर उनका मैं समर्थन करता हूं कि इस ग्राटिकल को हटाये जाने पर हमें ज़ोर देना चाहिये। जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा यह जो झंझट है यह हर मिनिस्टर को सहन पड़ेगा। इस वास्ते मैं मांग करता हुं कि इस ग्राटिकल को हटा दिया जाए ग्रौर ज़ो धन ग्रौर धरती हमारी पाकिस्तान में है उसको हम वापिस लें काश्मीर का ज़ो हिस्सा पाकिस्तान में है, वह हिस्सा हमें वापिस मिले। जो धन उनका यहां है उसको ग्राप रखिये ग्रौर उन से भी ग्राप लें।

ग्राज सुबह का नक्शा मैंने देखा है। राइट ग्रौर लैफ्ट के ज़ो कम्युनिस्ट भाई हैं उनके नक्शे को देखा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सचेत रहे। कहां ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं, इसको वह देखें। इनकी तरहफ से सावधान रहें :

मैं ग्राटिकल 370 के हटाये जाने की पुरज़ोर ग्रपील करता हूं। जो भी बैन ग्रापने जम्मू काश्मीर पर लागू किया है इस लिए मैं इसको ग्राप हटायें ग्रौर इस बिल को वहां भी लागू करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल ला कर ग्राप हमारे सामने पेश करें।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : इस बिल को लाने के लिए तो मैं मंत्री महोदय को मुबारिकबाद पेश करता हूं लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का बिल ग्राए इस बात का खयाल रखा जाय कि वह समय दूर नहीं

जबकि दोनों देशों को एक होना है। अगर ऋषियों की वाणी सही है, अरविन्दु घोष की वाणी सही है और हमारी ऐतिहासिक साइकोलोजी सच्ची है तो यह नामुम्किन है कि दोनों देश अलग अलग रह सकें। हमारी कौमियत एक है, हमारा खून एक है। गलतियों की वजह से हम दो देशों में बंट गए हैं। हम में से संकुचितता, जजबात, बिहरादरीवाद खत्म हो जाएगा, शराब बन्द हो जाएगी, अनटचेबलिटी बन्द हो जाएगी, छूआछूत खत्म हो जाएगी और दोनों देशों को एक होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा कदम न उठायें जिससे कि कल हम को पछताना पड़े। दोनों देशों की एकता लाजिमी है। यह कौम हो कर रहेगी। इसी के लिए रातदिन प्रयत्न हो रहे हैं।

कमजोरों के साथ कोई नहीं लग सकता है। जब तक कि भारत की मिलटरी स्ट्रैंग्थ नहीं बढ़ेगी तब तक पाकिस्तान हम से नहीं घबरायेगा। यहां हाउस में चर्चा आ चुकी है। हमारे सरस्वती नाम के जहाज को पाकिस्तान ने पकड़ा और पकड़ कर डिसफिगर किया और डिसफिगर करने के बाद उसका नाम जेबुन्निसा रखा। कमजोरों के साथ कोई लग नहीं सकता है। हमारी भारतीयता एक है। एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। मैं जिस सक्युलरिज्म का हामी हूं वह कौन सी सक्युलरिज्म है? महाराणा प्रताप के सिपहसालारे आजम, उनके प्रधान सेनापति का नाम हाकिम खां था। जब जननी जन्म भूमि पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो चित्तौड़ के किले को उसने टूटने नहीं दिया और अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया, उसकी उसने रक्षा की। चाहे दो अलग अलग देश अब बन गए हैं लेकिन अब भी हिन्दू हैं और मुसलमान हैं जोकि उस पाक मजार पर जा कर फूल चढ़ाते हैं। इस वक्त जो फिर्कापरस्ती है, वह सरमायादारकी पैदा की हुई है। हम में से जो नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी हैं, उन का यह फर्ज है कि वे इस फिर्कापरस्ती को खत्म करें। मैं वागहा पर देखता हूं कि पाकिस्तान की सरहद पर भी राजपूत का लड़का खड़ा है और हिन्दुस्तान की सरहद पर भी राजपूत का लड़का है। सरमायादार ने हम को बांटने के लिए एक का नाम मुस्लिम राजपूत और दूसरे का नाम हिन्दू राजपूत रख दिया। लेकिन हमारे खून में कोई फर्क नहीं है। हम एक हैं। धर्मशस्त्र और नीति शस्त्र कहता है, "श्रुतयोपि भिन्ना स्मृतयोअपि भिन्ना नैकः मुनीनां वचन प्रमाणम्"। इबादत और पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि पूजा के तरीके अलग अलग होने से कौमियत बंट जाती है, तो वह एक नामुकिन बात है।

जहां मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं, वहां मैं उन से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है कि जो झंडा गंगा पर लहरा रहा है, वही रावी पर भी लहरायेगा, जो झंडा दिल्ली पर लहरा रह है, वही पिंडी पर भी लहरायेगा। हमें एकता और राष्ट्रीयता कायम करनी पड़ेगी।

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): Some hon. members have said that article 370 must be removed. I am not supporting that because even after 22 years of independence, we have not been able to win over the confidence of the majority of Kashmiri people . . .

SHRI SRINIBAS MISRA: Who says so?

SHRI E. K. NAYANAR: I am saying that.

SHRI SRINIBAS MISRA: You cannot say that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That reference came incidentally.

SHRI SRINIBAS MISRA: That is against the Constitution itself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nayanar, if you have any submission to make regarding the Bill, you can.

SHRI E. K. NAYANAR: Even now there are differences of opinion. We should win over the people.

SHRI SRINIBAS MISRA: On a point of order. Nobody has a right to say here that India has not been able to win the confidence of the majority of Jammu & Kashmir people. Nobody has a right to make a statement like that because it is within the country.... (*Interruptions*).

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): On a point of order. What the hon. Member said was irrelevant.... (*Interruptions*).

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Article 370 is not under discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As I have already said, Mr. Sheo Narain just referred to this part . . .

SHRI E. K. NAYANAR: Most of the members referred to article 370 and said that it must be removed:

MR. DEPUTY-SPEAKER: We had a very lengthy debate on this very recently, if I remember correctly. Let us not take up that debate again.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a submission to make. If you say that Mr. Sheo Narain has said, am I to take it that he is the sole monarch of irrelevancy here?

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not fair.

श्री शिव नारायण : उपध्यक्ष महोदय, अगर इस हाउस में इस तरह से चलेगा, तो मैं इस से ज्यादा बदतमीजी कर सकता हूं। अगर ये गुंडागीरी करेंगे, तो मैं हाउस में बोलने नहीं दूंगा। जो बदतमीज आदमी है, मैं उसके साथ बदतमीज़ी कर सकता हूं। बेहुदापन का बेहूदा जवाब दिया जा सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nayanar, you may please sit down. The position has already been made clear. Mr. Sheo Narain just wanted to reply that unless something was done to remove article 370, nothing would happen and all these arguments in connection with the Bill would not carry us anywhere. Beyond that, he had nothing to say. ....(*Interruptions*).

SHRI E. K. NAYANAR: I am not raising the Kashmir problem at all. Some members said that article 370 must be removed. I am opposing that. That is all.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the Third Reading, such things should not be raised.

Article 370 is not before the House now.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI (Bilhaur): On a point of order. The previous speaker had just mentioned a few things which would have a tendency to create tension between India and Pakistan which are two separate countries. May I request the Members through you, Sir, to confine themselves strictly to the clauses of this particular Bill and not to take up other issues which are bound to create tension between the two countries?

श्री मोलहु प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए श्री शिव नारायण को बदतमीज़ी करने का अधिकार है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the hon. Member had not followed what Shri Sheo Narain had said. As I have said already, Shri S. M.

Banerjee unnecessarilly brought in some sort of cross-criticism. That is not fair.

So far as Shri Sheo Narain is concerned, on this occasion he was quite relevant, when he pointed out that unless that was done it would not be proper to amend the Bill. Beyond that he said nothing else.

श्री दिनेश सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य, श्री नायनार, ने इस बात की सफाई कर दी है कि काश्मीर भारत का अंग है। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में उन का यह कहना मुनासिब नहीं है कि वहां की जनता हमारे साथ नहीं है और न ही यह बात इस में आती है। अगर काश्मीर भारत का अंग है, तो वह भारत के साथ नहीं है, तो किस के साथ है? जाहिर है कि भारत के सब नागरिक भारत के साथ है?।

मैं उन तीन और माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। श्री भट्टाचार्य ने रिपोर्ट के सिलसिले में जिक्र किया था। मैंने उसके बारे में कल कहा था कि मैं देखूंगा कि किस प्रकार से हम यहां पर वह सूचना ला सकते हैं। लेकिन शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में हम बीच बीच सदन को सूचना देते रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बारे में एक विस्तृत सूचना होनी चाहिये। उस को भी हम देखेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस बिल को अपनी पूरी अनुमति देगा और यह बिल पास हो जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

14.58 hrs.

INTER-STATE WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, be taken into consideration."

As hon. Members are aware, there are many rivers in our country which pass through more than one State. Even when a river flows through one State there are always conflicts because the different farmers want to use the water for their own lands. When there are disputes within a State. those disputes are resolved by the State generally. In the case of disputes between different States, the Central Government try their best to solve the disputes. We have been doing that on a fairly big scale. But in one or two cases, the thing has got stuck up and I am very sorry that we have not been able to solve those problems.

So, in order to provide for the resolving of those disputes in such cases, an Act was passed by Parliament in 1956 called the Inter-State Water Disputes Act. In that Act, there is provision for only one judge. The tribunal was to consist of only one judge nominated by the Chief Justice of India, and the findings of that tribunal consisting of one judge was binding, and there was no appeal from that either to the Supreme Court or to Government. That finding was final and binding. Lately, we have been thinking that it would be much better if more collective wisdom and experience could be brought on to the question. The rivers are really the nation's treasures, and the nation's prosperity depends upon the economic way in which we develop

*Mover with the recommendation of the President.